भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1684
13.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाना

1684 **श्री हर्ष महाजनः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत देश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन एवं संबंधित अवसंरचना स्वीकृत/स्थापित की गई है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कितनी केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या राज्य के पर्वतीय एवं दूरदराज क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष नीति तैयार की गई है या अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): पीएम ई-ड्राइव स्कीम को कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय के साथ 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाए जाने को गति प्रदान करना है। यह स्कीम 24,79,120 ई-दुपहिया, 39,034 ई-रिक्शा और ई-कार्ट, 2,88,809 ई-तिपहिया (एल5), 5,643 ई-ट्रक और 14,028 ई-बसों सहित 28.27 लाख से अधिक ईवी को प्रोत्साहन देने में सहायता करती है। इस स्कीम के तहत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया (ई-रिक्शा और ई-कार्ट), ई-तिपहिया (एल5), ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों के लिए कुल 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की गई है। इसके अलावा, 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों में 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पूरे भारत में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस स्कीम के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। हालांकि, 07.02.2026 तक,हिमाचल प्रदेश में इस स्कीम के तहत कुल 1,187 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिनमें 1,050 ई-दुपहिया और 137 ई-तिपहिया शामिल हैं। वर्षवार संवितरित राशि का विवरण इस प्रकार है:

खंड	**वित्त वर्ष 24-25 में प्रोत्साहन प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहन**		**वित्त वर्ष 2025-26 में प्रोत्साहन प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहन (08.02.2026 तक)**	
	संख्या	**भुगतान की गई राशि (रुपये करोड़ में)**	**संख्या**	**भुगतान की गई राशि (रुपये करोड़ में)**
ई-दुपहिया	523	0.52	527	0.33
ई-तिपहिया	29	0.09	108	0.27
कुल	**552**	**0.61**	**635**	**0.60**

(घ): जी हां। सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत के पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट और वर्धित सहायता प्रदान की है। इनमें पहाड़ी राज्यों के लिए ई-बसों की गैर-ऑपेक्स खरीद मॉडल की अनुमति देना शामिल है।

*****